question of feasibility, what I said was that, according to the available data, the capacity utilisation of Faluknuma—Umdanagar section, which is only 13 kilometres, was 130 per cent. We can't think of introducing one more train there. In the same way, the Arakkonam-Renigunta section, which is 73 kilometres, is already exploited and saturation has reached the level of 140 per cent. That being the fact, we can't just think of, as of now, introducing one more train there. What I am trying to say is whether the capacity could be enhanced with reference to technical feasibility. On either side, we don't have pit lines, stable lines etc., and there is shortage of locomotives, etc. Further, Cuddapah is a wayside station. We don't have any facilities there. So, we are thinking on these lines.

MR. CHAIRMAN: That is enough. Next question, Shri Janeshwar Mishra.

नकली दवायें और सिंथेटिक दूध

*63. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर में नकली दवाओं और सिंथेटिक दूध का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सक्षम कानून है;

(ग) यदि हां, तो इन कानूनों के तहत किस सजा का प्रावधान किया गया है तथा गत तीन वर्षों के दौरान सजायाफ्ता लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ)यदि नहीं, तो सरकार कोई कानून कब तक बनायेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा॰ अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 की अवधि के दौरान 36947, 38824 और 36314 औषध नमूनों की जांच की गई थी जिनमें से क्रमश: 112, 96 और 125 नमूने नकली पाए गए थे जो कुल जांचे गए नमूनों का 0.3, 0.25 और 0.34 प्रतिशत है। इस प्रकार यह प्रतीत नहीं होता है कि देश भर में नकली औषधों के व्यापार में तेजी से वृद्धि हो रही है।

नकली औषधों की समस्या से निपटने के लिए औषध और समाधान अधिनियम, 1940 का 1982 में संशोधन किया गया था जिसके द्वारा अधिनियम में घटिया और नकली औषधों के विनिर्माण के लिए जुर्माने के साथ दण्ड जो 3 वर्ष के कारावास से कम नहीं होगा और जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के रूप में निर्धारित किए गए थे। तथापि, यदि औषध से मृत्यु अथवा गंभीर क्षति होती है और मृत्यु अथवा क्षति के लिए मिलावट की गई अथवा नकली औषध को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो प्रदान की गई सजा जुर्माने, जो 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, के साथ कम से कम 5 वर्ष का कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, होगी।

उक्त अधिनियम के अधीन, बेईमान व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने सहित औषधों के विनिर्माण और बिक्री को विनियमित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसके मद्देनजर राज्य औषध नियंत्रकों से उपलब्ध हुई सूचना के अनुसार 2000-01, 2001-02 और 2002-03 की अवधि के दौरान क्रमश: 651, 538 और 449 मुकदमें चलाए गए थे जबकि 245, 171 और 105 मामलों का निर्णय किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार 68 मामलों में दोष सिद्ध किया गया।

भारत सरकार ने नकली तथा घटिया औषधों के मुद्दे सहित औषध विनियामक प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने के लिए डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की। डा. माशेलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के दांडिक उपबंधों में संशोधन करने तथा मृत्युदंड की अधिकतम सजा सहित अपराधियों के लिए अधिक कठोर दंडों का प्रावधान करने के लिए दिसम्बर, 2003 में संसद में एक विधान प्रस्तुत किया गया था।

खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत 'सिंथेटिक दूध' की कोई परिभाषा नहीं है। ''सिंथेटिक दूध' सामान्यतया कोई भी व्यक्ति एक ऐसे उत्पाद का अर्थ लगाएगा जो अपने भौतिक, रासायनिक तथा पौषणिक लक्षणों में 'प्राकृतिक दूध' के सामान होता है। प्रेस द्वारा शुद्ध दूध तथा वनस्पति वसा, चीनी तथा रसायनों अर्थात् द्रव डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया, कास्टर आयल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम सल्फेट जैसे उपमिश्रकों के कृत्रिम काढ़े (कानकाक्शन) को ''सिंथेटिक दूध'' का नाम दिया गया है जिन्हें दूध की वसीय प्रतिशतता बढ़ाने के लिए उत्तरी राज्यों में बेईमान व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने की सूचना मिली है और जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम ''अपमिश्रित'' और ''गलत ब्रांड (मिस्ब्रांडिड) के साथ उत्पाद'' को परिभाषित करता है और ऐसे खाद्य उत्पादों के लिए दण्ड का प्रावधान करता है। यदि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता अथवा विशुद्धता निर्धारित मानदण्डों से कम है, और इसके संघटक ऐसी मात्रा में उपस्थित हैं जो परिवर्तिता की निर्धारित सीमाओं के भीतर नहीं हैं तो ऐसे खाद्य को

अपमिश्रित समझा जाता है। यदि कोई पदार्थ भ्रामक है अथवा सब्स्टीट्यूट है अथवा नकल है अथवा इस तरीके से मिलता जुलता है जिससे अन्य खाद्य पदार्थ, जिसके नाम के अंतर्गत उसे बेचा जाता है, को धोखा दिए जाने की संभावना हो, और जिस पर साफ साफ और स्पष्ट रूप से इसलिए लेबल नहीं लगया गया हो जिससे कि उसका सही पता चले अथवा उस पर झूठा लेबल लगा हो, तो यह गलत ब्रांड समझा जाता है।

दूध तथा दुग्ध उत्पाद जिनमें ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनका प्रावधान खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 में नहीं किया गया है, उनका खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अंतर्गत पहले ही प्रतिषेध किया जा चुका है। किसी अपमिश्रित तथा गलत ब्रांड की खाद्य सामग्री की बिक्री एक अपराध है जिसके लिए 6 माह के न्यूनतम कारावास तथा जुर्माना, जो 1000/- रुपये से कम नहीं होगा, की सजा दी जा सकती है। यदि अपमिश्रित खाद्य पदार्थ से मौत अथवा गंभीर क्षति होती है तो इस अपराध के लिए कारावास, जिसे आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना, जो 5000/- रुपये से कम नहीं होगा, की सजा दी जा सकती है।

Spurious drugs and synthetic milk

†*63. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the business of spurious drugs and synthetic milk is booming throughout the country;

(b) if so, whether there are any appropriate laws in this regard;

(c) if so, the punishment provided under these laws and the details of the convicted persons during the last three years; and

(d) if not, by when Government would enact a law?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

According to the information received from State Drugs Controllers, 36947, 38824 and 36314 drug samples were tested during the period 2000-01, 2001-02 and 2002-03 out of which 112, 96 and 125 samples respectively were found spurious which is 0.3, 0.25 and 0.34 per cent of

†Original notice of the question was received in Hindi.

the total samples tested. Thus, it does not appear that the business of spurious drugs is booming throughout the country.

In order to deal with the problem of spurious drugs, the Drugs and Cosmetics Act, 1940 was amended in 1982 whereby the penalties in the Act for manufacture of sub-standard and spurious drugs were prescribed as imprisonment of not less than 3 years which may extend to 5 years with fine. However, if the drug causes death or grievous hurt and this death or hurt is attributable to the drug being adulterated or spurious, then the punishment provided is imprisonment for not less than 5 years which may extend to a term of life and with fine which shall not be less than rupees ten thousand.

Under the said Act, the responsibility for regulating manufacture and sale of drugs including taking legal action against the unscruplous persons rests with the State Governments. In view of this, as per the information available from State Drugs Controller 651, 538 and 449 prosecutions were launched whereas 245, 171 and 105 cases were decided during the period 2000-01, 2001-02 and 2002-03 respectively. On the basis of available information, 68 cases resulted in conviction.

Government of India constituted a Committee of Experts under the chairmanship of Dr R.A. Mashelkar, DG, CSIR to undertake a comprehensive review of Drug Regulatory system including issue of spurious and substandard drugs. Based on the recommendations of Dr. Mashelkar Committee, a legislation to amend the penal provisions of Drugs & Cosmetic Act, 1940 and to provide for stricter penalties to the offenders including a maximum penalty of capital punishment, was introduced in the Parliament in December, 2003.

There is no definition of "synthetic milk" under the PFA Rules, 1955. By "synthetic milk" one would normally understand a product analogous to "natural milk" in its physical, chemical and nutritional properties. "Synthetic milk" is the name given by the Press to an artificial concoction of genuine milk and adulterants like vegetable fat, sugar and chemicals *i.e.* liquid detergent, caustic soda, urea, castor oil, hydrogen peroxide, sodium sulfate etc. that is reported to be used by some unscrupulous traders in some of the northern states to increase the fat percentage of milk and which is harmful to human health.

The PFA Act defines "adulterated" and "misbranded food product" and provides for punishment for such food products. The food is considered

as adulterated if the quality or purity of food article falls below the prescribed standards and its constituents are present in quantities not within the prescribed limits of variability. An article is considered as misbranded, if it is deceptive or a substitute or imitation or resembles in a manner likely to deceive another article of food under the name of which it is sold, and is not plainly and conspicuously a labeled so as to indicate its true character or is falsely labeled.

Sale of milk and milk product containing substances not provided in PFA Rules, 1955, is already prohibited under the provisions of Prevention of Food Adulteration Act, 1954. Sale of any adulterated and misbranded article of food is an offence punishable with minimum imprisonment of six months and with fine which shall not be less than Rs. 1000/-. In case adulterated food stuff causes death or grievous hurt, the offence is punishable with imprisonment which may extend to term of life and with fine which shall not be less than Rs. 5000/-

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, यह मामला अपने आप में बहुत गंभीर है। हम चाहते हैं कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार ने एक कमेटी, दवा में मिलावट और नकली दवा बेचने की जांच करने के लिए बनाई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि जो लोग दवा में मिलावट करते हैं, उनको फांसी की सजा दी जाये। पिछली सरकार में श्रीमती सुषमा स्वराज स्वास्थ्य मंत्री थीं। फांसी की सजा के प्रावधान को पिछली सरकार के मंत्रिमंडल में स्वीकृत किया गया था। उसके बाद से कई तरह की क्रिया-प्रतिक्रियाएं अखबारों में आई हैं। यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि कई अरब डालर की नकली दवाएं दुनियाभर में बिक रही हैं और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बिक रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया था, क्या वर्तमान सरकार उसके बारे में सदन में बिल पेश करेगी?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Mr. Chairman, Sir, I understand and concur with the concerns of the hon. Member of Parliament. A Bill was moved in the last session of the Parliament. Since we have another new Government at this time, this will be taken up with the Cabinet.

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मुझे एक सवाल और पूछना है। यह कोई जवाब तो हुआ नहीं, लेकिन देखा जायेगा। सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, उसे देखते हुए इसको आश्वासन समिति को रेफर कर दिया जाये । ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम: चेयरमैन सर, रिपोर्ट पर चर्चा होती है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: उनको सवाल पूछने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : लोक सभा भंग हो गई, इसलिए बिल दुबारा पेश करना पड़ेगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : मंत्री जी, नये हैं, सरकार नयी है। आप कुछ तो रियायत करिये। ...(व्यवधान)...

श्री जनेश्वर मिश्र: सर, उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि देश में 600 से ज्यादा जिलों में चार लाख से ऊपर दवा की लाइसेंस वाली दुकानें चल रही हैं और उन दुकानों की जांच के लिए केवल 800 ड्रग इन्सपेक्टर हैं। वे इतनी दुकानों की कैसे जांच कर सकते हैं? मशीनें भी कम हैं, जो जांच किया करती है। इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इनकी तादाद बढ़ायी जाये और साथ ही साथ मशीनों की तादाद भी बढ़ायी जानी चाहिए। सर, दवा के कैपसूल में कहीं-कहीं आटा, कहीं-कहीं बालू भर दिया जाता है और ये मौत के सौदागर रुपया कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पूरा सदन इसको गंभीरता से ले और सरकार भी इसको गंभीरता से ले।

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Mr. Chairman, Sir, I agree with the hon. Member. Accordingly, we are going in for a capacity-building project funded by the World Bank. We are going to spend Rs. 356.25 crores on capacity building, improving the infrastructure and lab facilities and training manpower. The State Drugs Authorities are supposed to be enforcing this.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Mr. Chairman, Sir, The Minister has just said that a Bill is pending before the other House. Till the Bill is passed by both the Houses of Parliament and becomes an act, what measures will the Government take to check the use of spurious drugs. Last week, there were a lot of reports about the death of a number of children in the Safdarjung Hospital. Were those deaths due to the use of spurious drugs or due to negligence?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, those deaths in the Safdarjung Hospital have nothing to do with spurious drugs.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Do you have a report?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: I had ordered an inquiry after those reports in the Press. Sir, those deaths were normal deaths which occur day-to-day.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, how can deaths be normal? It is very funny.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: सभापति महोदय, प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक तो नकली दवाओं के संबंध में है और दूसरा सिंथेटिक मिल्क के बारे में है। मैं सिंथेटिक दूध के बारे में पूछना चाहती हूं कि इस देश में किसी दूध की नदियां बहती थीं लेकिन आज सिंथेटिक दूध बह रहा है। दूध के जो सोर्स हैं वे प्राय: तीन हैं। सरकारी, गैर-सरकारी और निजी ग्वालों के द्वारा घरों में। क्या सरकार ने इस तरह का कोई सर्वेक्षण करवाया है कि जिसे आप सिंथेटिक मिल्क न कहकर एडलट्रेटिड मिल्क कह रहे हैं, वह कहां-कहां पाया जा रहा है और किस मात्रा में है? क्या इस प्रकार के कार्य में किसी को भी अभी तक पकड़ा गया है और अगर पकड़ा गया है तो सजा हुई है या नहीं?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, samples of milk are being examined right from the year 1999. I have a list before me. I can give it to the hon. Member. If you permit me, I can read it out.

श्री संजय निरुपम: बताइए कि कौन-कौन से एरियाज हैं?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: So far as testing of milk samples is concerned, it is a State subject. The State authorities have to take samples and do the testing all over India. We monitor it. As I said before, we have some problem so far as infrastructure is concerned. But we are going to build infrastructure with the help of the World Bank.

श्री अमर सिंह: कब तक आप इनफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे? बच्चों की डेथ कब तक होती रहेगी?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: The State Drugs Controller is incharge of ...(*Interruptions*)

श्री सभापति: आप अभी कौन-सा दूध पीकर आए हैं जो इतनी जोर से बोल रहे हैं।

श्री अमर सिंह: सर, उत्तर प्रदेश का असली दूध।

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, in 1999, the number of samples examined was 5477; adulteration was found in 1568 samples and the percentage was 28.62. In 2000, the number of samples examined was 5331; adulteration was found in 1597 samples and the percentage was 29.95. In 2001, the number of samples examined was 6188; adulteration was found in 2056 samples and the percentage was 33.22. In 2002, the number of samples examined was 2630; adulteration was found in 692 cases and the percentage was 26.31. For the year 2003, we are yet to get

the report. Till now, the number of samples examined is 1760 and adulteration is found in 472 samples and the percentage is 26.81.

Sir, the number of prosecutions in 1999 was 5114 and the number of cases decided by courts was 2935; 1214 persons were convicted and 1721 were acquitted. In 2000, the number of prosecutions was 4532; the number of cases decided by courts was 2373; 789 persons were convicted and 1584 were acquitted. In 2001, the number of prosecutions was 5943, the number of cases decided by courts was 2704; 1263 persons were convicted and 1441 were acquitted. In 2002, the number of prosecutions was 2867 and...

MR. CHAIRMAN: You lay this statement on the Table of the House.

Opening of hospitals on the pattern of AIIMS

*64. SHRIMATI VANGA GEETHA:†
PROF. M.M. AGARWAL:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether six more institutes like AIIMS are being planned to be set up in backward areas;

(b) if so, the details of the places selected and progress achieved in this regard;

(c) the details of the funds allotted, released and actually utilized on the construction of these hospitals during the year 2003-04 and till date;

(d) the details of facilities alongwith the total beds to be provided by the above hospitals; and

(e) by when, the above hospitals are likely to be commissioned?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Last year, a scheme called Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna was formulated wherein it was decided in-principle to set up one AIIMS-type institution each in the States of Bihar (Patna), Chhattisgarh (Raipur), Madhya Pradesh (Bhopal), Orissa (Bhubaneshwar), Rajasthan

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Vanga Geetha.